

प्रेषक,

दमयन्ती चौहरे
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून: दिनांक 25 मार्च, 2008

विषय:- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में स्वीकृत कलस्टर में विवादित योजना के स्थान पर नयी योजनाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 528/ल०सि०/ए०आई०बी०पी०/2006-07 दिनांक 23.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं० 1210/11-2005-04(02)/04 दिनांक 28.11.2005 के सलग्नक के जनपद अल्मोड़ा के क्र०सं० 33, 35, 59 एवं 63 तथा जनपद उत्तरकाशी के क्र०सं० 434, 451, 456, 459 एवं 460 पर उल्लिखित कलस्टर में विवादित उपयोजनाओं (सलग्नक के कालम-5 पर अंकित योजनायें) को निरस्त करते हुए सलग्नक के कालम-7 पर अंकित योजनाओं, जिनकी लागत रु० 54.50 लाख (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र) है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- योजनाओं का कार्य कराते समय बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, रटोर पर्चेज क्लर्क तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में ली गयी लीड दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दूरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।
- 4- कार्य सम्पादित कराते समय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- 5- इन योजनाओं का वित्त पोषण शासनादेश सं० 1210/11-2005-04(02)/2004 दिनांक 28.11.2005 के सलग्नक के जनपद अल्मोड़ा के क्र०सं० 33, 35, 59 एवं 63 तथा जनपद उत्तरकाशी के क्र०सं० 434, 451, 456, 459 एवं 460 पर उल्लिखित कलस्टर में विवादित उपयोजनाओं (सलग्नक के कालम-5 पर अंकित योजनायें) के लिए स्वीकृत धनराशि से ही किया जायेगा और इस शासनादेश के द्वारा इन योजनाओं के लिए कोई व्यय की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, केवल प्रशासनिक स्वीकृति ही दी जा रही है।
- 6- धन की उपयोगिता का प्रमाण पत्र कार्यवार व्यय विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाय।
- 7- योजना के क्रियान्वयन के समय ए०आई०बी०पी० की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

कमश:.....2

(2)

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 549 (P)/XXVII-4 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव।

संख्या: - 379 / II-2008-03 (13) / 2004 / तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सीनियर ज्वाइंट कमिशनर (एम0आई0) जल संसाधन, मंत्रालय, 108 बी0 शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कोषाधिकारी, अल्मोडा एवं उत्तरकाशी।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल हेतु।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

